'कांग्रेसराज में सरपंच आंदोलन करते थे,अब मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे'

बिना भेदभाजपा विकास की राजनीति करती है तो कांग्रेस डालती है व्यवधान : पंचायतीराज मंत्री

जयपुर । पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं में बेसिर पैर की बातें करने की होड़ मची हुई है। यही कारण है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी समाप्त होती जा रही है। जल्द ही कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन विपक्ष के रूप में जानी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ही डोटासरा अकेले पड़ते जा रहे हैं तथा उनकी नेगेटिविटी भी बढ़ती जा रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय सरपंच जयपुर में आंदोलन करना पड़ता था लेकिन अब प्रदेशभर के सरपंचों के द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया जा रहा है क्योंकि भजनलाल सरकार ने पंचायती राज को मज़बूत किया जबकि कांग्रेस ने पंचायती राज को कमजोर किया।

पंचायती राज मंत्री ने कहा कि भाजपा विकास की राजनीति करती है तो कांग्रेस व्यवधान की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि एक राज्य एक चुनाव केवल चुनावी सुधार नहीं बल्कि प्रशासनिक स्थिरता एवं विकास की तरफ मजबूत कदम है।

उन्होंने कहा कि पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में जिला परिषद का प्रावधान है। हमारी सरकार ने जिलों के पुनर्निर्धारण के साथ ही नई जिला परिषद के गठन की कार्यवाही शुरू कर दी। जबकि कांग्रेस सरकार ने नए जिलों में जिला परिषद के गठन का कोई काम ही नहीं किया।

राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम की धारा 98 के तहत सभी जिला कलेक्टर्स को अधिकृत कर पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु अधिकृत किया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में विलंब को देखते हुए एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार ही निवर्तमान सरपंच को प्रशासक लगाया गया है। साथ ही, निवर्तमान उपसरपंच व वार्डपंचों की प्रशासकीय समिति बनाई गई है। इसके लिए झारखण्ड, मध्यप्रदेश व उत्तराखण्ड राज्यों में की गई इस तरह की व्यवस्था का पहले अध्ययन करवाया गया।

दिलावर ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं में ओबीसी के आरक्षण को अटकाने का काम किया। मनमोहन नागर बनाम मध्यप्रदेश याचिका में 17 दिसम्बर 2021 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात भी ओबीसी आरक्षण के संबंध में तत्कालीन सरकार द्वारा दो वर्ष तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग मद से वर्ष 2023-24 में कुल जारी होने योग्य राशि 3808 करोड की सभी स्वीकृति जारी कर दी गई हैं। वर्ष 2024-25 कुल जारी होने योग्य राशि 6072 करोड में से प्रथम किश्त की राशि 3036 करोड रूपए जारी कर दी गई है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा पंचायतीराज विभाग में नियमानुसार ही स्थानांतरण किए जा रहे हैं। कांग्रेस की बातें पूर्णतः तथ्यहीन, मिथ्या एवं भ्रामक हैं।

"जल जीवन मिशन" में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचा रही केन्द्र सरकार : राठौड़

जयपुर। केन्द्र सरकार देश के हर घर में शुद्ध पेयजल की सप्लाई के लिए प्रयास कर रही है और इसके लिए वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की शुरूआत की गई है। साथ ही देशभर में बनाए गए 15 हजार 259 निगरानी स्थलों से नमूने लेकर भूजल में विद्युत चालकता, फ्लोराइड, आर्सेनिक, भारी धातुओं और नाइट्रेट की मात्रा की जांच की जा रही है। अब तक की जांच रिपोर्ट में कई स्थानों पर भूजल में इनकी मात्रा तय मानकों से अधिक पाई गई है। यह जानकारी केन्द्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री राजभूषण चौधरी ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड के लिखित प्रश्न के जवाब में दी।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड ने बताया कि केन्द्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री राजभूषण चौधरी के अनुसार भूजल की जांच रिपोर्ट में अब तक किसी नए प्रदूषक की पहचान नहीं हुई है। वहीं भूजल गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण कम करने सहित भूजल की उपलब्धता की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और केन्द्र सरकार की ओर से देश के सभी राज्यों को इसमें पूरा तकनीकी और वित्तीय सहयोग किया जा रहा है।

एकल पट्टा : नये तथ्यों के साथ जाँच के लिये प्रार्थना पत्र पेश

राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में पूर्व जस्टिस आर.एस. राठौड़ की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जाँच की अनुमति मांगी

- एजी ने कहा कि अधूरी व दोषपूर्ण साक्ष्यों पर की गई जाँच के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई थी। अब जस्टिस राठौड़ की कमेटी रिपोर्ट से स्पष्ट है, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने में गंभीर चूक हुई है।

जयपुर । प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में पूर्व जस्टिस आरएस राठौड़ की कमेटी की जांच में नए तथ्य सामने आने पर राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर इन तथ्यों के आधार पर आगामी जांच की अनुमति मांगी गई है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से उस रिवीजन याचिका को भी वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें राज्य सरकार ने मामले में पूर्व आईएएस जीएस संधू, ओंकार मल सैनी और निष्काम दिवाकर के अभियोजन को वापस लेने के प्रार्थना पत्र को एसीबी कोर्ट के खारिज करने को चुनौती दी गई है।

राज्य सरकार एएजी शिवमंगल शर्मा व विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने बताया कि इन अर्जियों में कहा है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर क्लोजर रिपोर्टस अधूरी व दोषपूर्ण साक्ष्यों पर की गई जांच के आधार पर थीं और इसके चलते ही पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को मामले में राहत मिली थी।

इसके अलावा, मामले में जांच के लिए गठित हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस आरएस राठौड़ की कमेटी ने भी इस मामले की समीक्षा कर रिपोर्ट दी है, जिसमें कई नए तथ्यों का खुलासा किया गया है। ऐसे में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने में गंभीर चूक हुई थी, जिससे महत्वपूर्ण दस्तावेजों और ठोस सबूतों की अनदेखी की गई। इसलिए राज्य सरकार ने इन गलतियों को सुधारने व भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की इन अर्जियों पर चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की एकलपीठ 10 फरवरी को सुनवाई करेगी।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अशोक पाठक की एसएलपी पर, इस मामले में 5 नवंबर 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट के 15 नवंबर 2022 व 17 जनवरी 2023 के उन आदेशों को रद्द कर दिया था, जिनमें पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल व पूर्व आईएएस जीएस संधू सहित, जेडीए के तत्कालीन अफसरों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई खत्म कर दी थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को समीक्षा के लिए वापस राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवाते हुए उन्हें कहा था कि वे इसमें नए सिरे से सुनवाई कर छह महीने में फैसला दें।

हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बैठक

चंडीगढ़ । हरियाणा के पंचकूला पार्टी कार्यालय "पंचकमल" में बुधवार को नगर निकाय चुनाव और संगठनात्मक विषयों को लेकर भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की रणनीति और संगठनात्मक विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में सहमति बनी कि भाजपा नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव सिंबल पर लडेगी।

कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सांसद सुभाष बराला, मंत्री कृष्ण बेदी, संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री डा. अर्चना गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता रामबिलास शर्मा, सुनीता दुग्गल, पूर्व मंत्री डा. कमल गुप्ता मौजूद रहे।

हरियाणा के पंचकूला पार्टी कार्यालय में भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया को पुष्पगुच्छ भेंट किया।

कोर ग्रुप की बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव, सिंबल पर लडेगी। उन्होंने कहा कि मेयर और चेयरमैनों के चुनाव डायरेक्ट होने हैं। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से आवेदन मांगे गए हैं। 11 फरवरी से नोमिनेशन शुरू होने हैं, इसलिए एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत तय है। भाजपा नगर निगम और नगर परिषद चुनाव सिंबल पर लडेगी। पूनिया ने कहा कि भाजपा नगर निगमों को लेकर अलग-अलग संकल्प पत्र जारी करेगी।

'शाहपुरा में सूखे और खराब नलकूपों को दुरुस्त कराएंगे'

जयपुर । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में सूखे एवं खराब नलकूपों को जल जीवन मिशन के तहत प्राथमिकता से दुरुस्त कराया जाएगा। जलदाय मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 43 नलकूप ख़राब पाए गए। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा 3400 किमी की केसिंग पाइपलाइन के लिए लगभग 96 लाख रूपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के तहत 05 नलकूपों की स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा ये सभी कार्य प्राथमिकता से पूरे कर लिए जाएंगे।

चौधरी ने सदन को अवगत कराया कि शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के तहत 83 योजनाओं में 142 नलकूप स्वीकृत हैं। इनमें से 26 नलकूप सूखे पाए गए हैं। इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत 76 संशोधित योजनाओं में 163 नलकूप स्वीकृत है एवं 12 सूखे नलकूपों को आवश्यकता के आधार पर संवेदकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर दुरुस्त कराया जाएगा। इससे पहले विधायक मनीष यादव के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में विभिन्न पेयजल योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में 22 नलकूप सूखे हैं। जिनमें से 01 नलकूप के विरूद्ध नवीन नलकूप स्वीकृति उपरांत निर्मित करवाया जा चुका है एवं 04 नलकूपों के विरूद्ध नवीन नलकूपों के निर्माण की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है एवं जिनका कार्य प्रगति पर है। इनका शहर/ग्रामवार विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने जानकारी दी कि शेष 17 नलकूपों में से शहरी क्षेत्र के 07 नलकूपों के विरुद्ध नवीन नलकूपों के निर्माण हेतु स्वीकृतियां तकनीकी उपादेयता भू-जल उपलब्धता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जारी की जानी प्रस्तावित है।

विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को उनके जन्मदिवस पर पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। देवनानी ने बुधवार को प्रातः सदन को भी गर्ग के जन्मदिवस के संबंध में अवगत कराया। जिसके बाद पूरे सदन ने उन्हें बधाई दी थी।

रिलायंस फ्रेश को देना होगा 15 हजार रुपए का हर्जाना

- 7.40 रु. अधिक वसूलने पर चुकानी होगी यह रकम

जयपुर, 5 फरवरी। जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम ने दही की तय कीमत से 7.40 रुपए अधिक वसूलने को विक्रेता की लापरवाही और अनुचित व्यापार माना है। इसके साथ ही आयोग ने विपक्षी रिलायंस फ्रेश पर 15 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

वहीं अधिक वसूली गई राशि भी परिवाद दायर करने की तिथि से 9 फीसदी ब्याज सहित लौटाने को कहा है। आयोग अध्यक्ष डॉ. सूबे सिंह यादव और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश रामचरण जोशी की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए। आयोग ने कहा कि विपक्षी दुकानदार ने अधिक कीमत वसूल कर उपभोक्ता का न केवल विश्वास तोडा है, बल्कि यह अनुचित व्यापार की श्रेणी में भी आता है। ऐसे में उस पर हर्जाना लगाना उचित होगा।

परिवाद में कहा गया कि उसने 3 मई, 2022 को रिलायंस फ्रेश से मदर डेयरी ब्रांड का 200 ग्राम क्लासिक दही खरीदा था। जिसके पैकेट पर अधिकतम खुदरा मूल्य 22 रुपए अंकित था। इसके बावजूद भी दुकानदार ने उससे 29.40 रुपए वसूले। परिवादी ने जब उससे लिए गए अधिक रुपए लौटाने को कहा कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। परिवाद में गुहार की गई कि उससे वसूली गई अधिक राशि लौटाने के निर्देश देते हुए दुकानदार पर हर्जाना भी लगाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने विपक्षी दुकानदार पर हर्जाना लगाते हुए अधिक वसूली राशि ब्याज सहित लौटाने को कहा है।

प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही लोकतंत्र की पहली सीढ़ी को मजबूत

- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बयान दिया
- कांग्रेस काल में लूटमार और भ्रष्टाचार का हुआ खुल्ला खेल था : खाद्य मंत्री

जयपुर । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस चार गुटों में बंटी हुई है तथा कांग्रेस के नेता झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में जो लूटमार और भ्रष्टाचार का खुल्ला खेल हुआ, उसको अब भजनलाल सरकार जनता के सामने ला रही है, तो कांग्रेस तिलमिला रही है। गोदारा ने कहा कि डोटासरा अकेले पड़ते जा रहे तथा उन्हें छपास का रोग लग चुका है।

उन्होंने कहा कि प्रदेशभर से इतनी बड़ी संख्या में सरपंचों का जयपुर में एकत्रित होना कांग्रेस के लिए अचंभे की बात है। चूंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए पंचायतों का मुद्दा उठा रही है। उनकी तब की सरकार ने बिना सोचे समझे जिलों का पुनर्गठन किया। अब नए जिले बनाए जाने के कारण ही पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लोकतंत्र की पहली सीढ़ी को मजबूत करने का काम पहली बार हो रहा है। हमारी सरकार ने एक वर्ष में ही कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। जिससे वंचित वर्ग से लेकर उद्योग जगत तक हमारी सरकार की योजनाएं पहुंची हैं और उनको लाभ मिला है। हमारी सरकार के किये गये कार्यों से जनता खुश है तभी पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए सरपंच संघों ने जयपुर में आकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया। जबकि इससे पहले सरपंच संघ जयपुर में आंदोलन करने आते थे।

गोदारा ने कहा कि सरपंच किसी पार्टी के नहीं होते हैं, सरपंच सरकार की योजनाओं को गांव तक डिलीवर करने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। किसी की समस्या का समाधान करने के लिए उसकी पीड़ा को समझना पड़ता है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरपंचों की पीड़ा को अनुभव किया है। अब सरपंचों को मज़बूत किया जा रहा है तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है। पंचायतों को सशक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि ये संस्थाएं लोकतंत्र के सबसे निचले स्तर पर लोगों तक शासन का प्रभावी तरीके से संचालन करती हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का ही परिणाम है कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

पूर्व कांग्रेस विधायक की जमीन से जुड़े सवाल पर हंगामा

जयपुर। पूर्व कांग्रेस विधायक खुशवीर सिंह जोजावर पर जमीन हड़पने से जुड़े सवाल को लेकर सदन में प्रश्नकल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पहले भाजपा विधायक केसाराम चौधरी ने राजस्व मंत्री के जवाब को अधूरा बताते हुए नाराजगी जताई और कहा कि यह सही जवाब नहीं है। इसके बाद राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि ओरण की जमीन का आवंटन हुआ है। इसमें खुशबीर सिंह जोजावर और अन्य लोग शामिल हैं। इसी बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा- कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, इन्होंने भगवान की जमीन को भी नहीं छोड़ी, उसे भी हड़प लिया। पूर्व कांग्रेस विधायक का नाम आने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताते हुए कहा कि, इस तरह के आरोप लगाने का किसी को अधिकार नहीं है। इस पर मदन दिलावर और टीकाराम जूली के बीच नोंक-झोंक हो गई। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सब कुछ शांत रहने को कहा। स्पीकर ने कहा कि लगता है आप सदन नहीं चलाना चाहते।

सरकार ने 8 आई.ए.एस. को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी

जयपुर (कासं)। राज्य सरकार ने बुधवार को आदेश जारी कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। आदेश के मुताबिक कुलदीप रांका को बाल अधिकारिता विभाग के आयुक्त व अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा राज्य बाल अधिकारिता विभाग के अध्यक्ष पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। इसी तरह आई.ए.एस. श्रेया गुहा को स्वयंसेवी एवं आजीविका संस्थान जयपुर की स्टेट मिशन डायरेक्टर, आरूषि अजेय मलिक को राजसीको के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है।

इसी प्रकार आई.ए.एस. शिवांगी स्वर्णकार को दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राजस्थान जयपुर के आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के कमिश्नर के पद की जिम्मेदारी दी है। सुरेश कुमार ओला को वित्त विभाग जयपुर में संयुक्त सचिव, बचनेश कुमार अग्रवाल को दिव्यांगता विभाग के आयुक्त एवं विशेष सचिव तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन जयपुर के डायेक्टर जनरल पद की जिम्मेदारी सौंपी है। आई.ए.एस. शाहीन अली खान को स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी जयपुर के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डॉ. टी. शुभमंगला को चिकित्सा विभाग (आई.ई.सी.) में निदेशक तथा अरूण प्रकाश शर्मा को प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, आर.पी.जी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में संयुक्त सचिव के पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है।

पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव 14 को

जयपुर । राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव 14 फरवरी को कराये जायेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव नलिनी कठोतिया के अनुसार निर्वाचन की लोक सूचना गत 29 जनवरी को जारी हो चुकी है एवं मतदान 14 फरवरी को होगा।

यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में 1600 करोड़ का औद्योगिक पार्क लगाएगा पतंजलि ग्रुप

इससे करीब 3 हजार से अधिक रोजगार सृजन होगा : आचार्य बालकृष्ण

जयपुर (कासं)। पतंजलि ग्रुप यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अपने औद्योगिक विस्तार को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, आचार्य बालकृष्ण प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 24 पहुंचे, जहां उन्होंने पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क की आगामी योजनाओं पर चर्चा की। यह प्रमुख परियोजना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश और रोज़गार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। इस पार्क में एक अत्याधुनिक डेयरी प्लांट और औद्योगिक प्रमोशन हब स्थापित किया जाएगा, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

पतंजलि की ओर से स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक पार्क को लेकर आचार्य बालकृष्ण ने उद्योग जगत के विशेषज्ञों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

इस मौके पर आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि यह औद्योगिक पार्क 1600 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मेक इन इंडिया" अभियान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के "इन्वेस्ट यूपी मिशन" के अनुरूप है। पूरी तरह से कार्यशील होने पर, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क से 3000 से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा।

पतंजलि ग्रुप पहले से ही एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है, जहां छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों को सब-लीज के माध्यम से औद्योगिक स्पेस उपलब्ध कराया गया है। आगामी फूड एंड हर्बल पार्क इस पहल को और मजबूती देगा, जिससे एफएमसीजी, आयुर्वेद, डेयरी और हर्बल उद्योगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और स्थानीय स्तर पर औद्योगिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा। औद्योगिक पार्क का दौरा करने के बाद, आचार्य बालकृष्ण ने उद्योग जगत के विशेषज्ञों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अरुणवीर सिंह, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।

'थानागाजी में भू-जल आधारित योजनाओं की स्वीकृतियां जारी'

जयपुर । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैया लाल ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र थानागाजी की कुल 58 ग्राम पंचायतों के 237 ग्रामों एवं चिन्हित 672 ढाणियों में से 197 ग्रामों एवं 671 ढाणियों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु भू-जल आधारित योजनाओं की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बुधवार को प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक कांति प्रसाद के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र थानागाजी के 18 ग्रामों एवं उनकी 66 ढाणियों को लाभान्वित करने के लिए स्वीकृत 18 योजनाओं के कार्य, भू-जल स्त्रोत सस्टेनेबल नहीं होने के कारण प्रारंभ नहीं करवाये गये हैं। श्री कन्हैया ने कहा कि जल जीवन मिशन में केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गांव एवं बस्तियों से दूर खेतों में स्थित एकल घरों के अतिरिक्त क्षेत्र के समस्त ढाणियों को जोड़ा जा रहा है।

कहा कि गर्मी के समय जल स्त्रोतों में जल की अनुपलब्धता होने पर पानी के टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि थानागाजी विधानसभा के 58 ग्रामों एवं 67 ढाणियों को ईसरदा बांध परियोजना अथवा ईआरसीपी परियोजना से सतही जल उपलब्ध होने पर लाभान्वित किया जाएगा।

"उपचुनाव में डोटासरा का मोरिया बोल गया"

जयपुर (विसं)। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि हमारे साथी कैलाश वर्मा ने गोविंद सिंह डोटासरा के गमछा घुमाने की बात का जिक्र किया था। मैं कहूंगा कि, लोकसभा चुनाव में डोटासरा ने संविधान के नाम पर लोगों को भड़काकर राजस्थान में 11 सीटें जीत ली, लेकिन उपचुनाव में मोरिया बोल गया। कृपलानी ने कहा कि ये जहां-जहां भी गए कांग्रेस साफ हो गई। हरियाणा, महाराष्ट्र, जहां भी गमछा घूमा, वहां कांग्रेस साफ हो गई। डोटासरा ने राज्यपाल की उम्र को लेकर भी टिप्पणी की। राज्यपाल ने भी इन्हें जवाब देकर औकात दिखा दी।